

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9

अंक 19

1-15 अक्टूबर 2026

₹ 20/-

एएमयू के बाद जामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग तेज



- तेलंगाना में मदरसों और मुस्लिम संगठनों की जांच शुरू
- खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार बर्खास्त

- इराक से अमेरिकी सेना की वापसी
- अजरबैजान के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध

सारांश

पिछले कई दिनों से देश के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर आंदोलन जोरों पर है। एएमयू प्रशासन लगभग आठ वर्ष के अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव करवाने पर सहमत हो गया है। इसके साथ ही छात्रों ने अपना धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल वापस ले ली है। दूसरी ओर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्थिति दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में पिछले 20 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव कराने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के जरिए छात्रों द्वारा यह मांग की जा रही है कि यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ को बहाल कर चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाए। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर विचार करने और छात्रसंघ का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन छात्रों द्वारा चुनाव की निश्चित समय-सारिणी की मांग पर अड़े रहने के कारण गतिरोध अभी तक बना हुआ है।

पाकिस्तान में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) की खैबर पख्तूनख्वा सरकार को बर्खास्त कर प्रांत में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी समेत उनके पूरे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब प्रांत का प्रशासनिक संचालन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से जुड़े राज्यपाल फैसल करीम कुंडी के हाथों में आ गया है और उनकी सहायता के लिए एक 11 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

दो दशक के बाद अमेरिकी सरकार ने इराक से अपनी सेना को पूरी तरह से वापस बुला लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2003 में सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्तापलट करने के लिए इराक में सेना भेजी थी, जिसने बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई थी। इससे पहले वर्ष 2011 में भी अमेरिकी सेना इराक से वापस चली गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए फिर से इराक लौट गई। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिकी सेना की इस अंतिम वापसी के बाद इराक की समस्या और भी उलझ गई है, क्योंकि इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र मिलिशिया गुट लंबे समय से सक्रिय हैं और वे अभी तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहे थे। इराक सरकार ने यह आशा व्यक्त की थी कि ये सशस्त्र संगठन निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इन मिलिशिया गुटों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके अतिरिक्त आईएसआईएस के आतंकवादी फिर से वहां सक्रिय हो रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद आईएसआईएस इस क्षेत्र में फिर से उत्पात मचा सकता है।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच जारी युद्ध भीषण रूप ले चुका है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं, जिनमें अब तक हजारों लोग मारे गए हैं। हूती विद्रोहियों के अत्याधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद समेत कई तेल संयंत्रों को निशाना बनाया है, जिसके कारण सऊदी अरब का तेल कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्किये के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत इन देशों से सैन्य सहायता मांगी थी, लेकिन अभी तक ये दोनों देश इस युद्ध से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं, अमेरिका इस विवाद से दूर रहना चाहता है, इसलिए उसका यह प्रयास है कि सीरिया सरकार सऊदी अरब की सहायता के लिए अपनी सेना को मैदान में उतारे। हाल ही में विदेशी मीडिया ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि चीन हूती विद्रोहियों को दूर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के कल-पुर्जों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे वे न केवल सऊदी अरब, बल्कि इजरायल को भी निशाना बना सकते हैं।

एएमयू के बाद जामिया में छात्रसंघ बहाली की मांग तेज



देश के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर पिछले कुछ समय से व्यापक छात्र आंदोलन चल रहा है। हालांकि, जहां एएमयू ने छात्रसंघ का चुनाव करवाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच गतिरोध और गहरा गया है। एएमयू प्रशासन द्वारा चुनाव की तारीख घोषित किए जाने के बाद वहां के छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

हमारा समाज (10 अक्टूबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा पिछले 19 दिनों से चलाया जा रहा आंदोलन यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उनकी सभी मांगें माने जाने के बाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। यूनिवर्सिटी की उपकुलपति प्रो. नईमा खातून ने स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों को जूस पिलाया और उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। इस निर्णय से पहले यूनिवर्सिटी

के छात्रों और प्रबंधन के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद नावेद खान को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रो. मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी को नया प्रॉक्टर नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त विधि विभाग के प्रो. जावेद तालिब को छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, वीमेंस कॉलेज के अंडरग्रेजुएट छात्रसंघ चुनाव को स्वतंत्र रूप से कराने के लिए अंग्रेजी विभाग की प्रो. नाजिया हसन को अलग से मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन के इस कदम के बाद कैंपस में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है।

उर्दू टाइम्स (19 अक्टूबर) के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।



छात्रों का दावा है कि 17 अक्टूबर की सुबह लगभग पांच बजे यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मियों ने दिल्ली पुलिस की सहायता से उन्हें धरना स्थल से जबरन हटा दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के दौरान सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के जवान यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ मौजूद थे।

कैंपस में छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) की जामिया ईकाई के सचिव एबिन बासिल ने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके और प्रदर्शन स्थल पर मौजूद अन्य छात्रों के साथ मारपीट की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए परिसर के सभी मुख्य द्वारों को बंद कर दिया।

जामिया प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे एबिन बासिल को एक साल के लिए निष्कासित कर दिया है और दो अन्य छात्रों के कैंपस में प्रवेश करने पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों पर बल प्रयोग या मारपीट करने के आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। प्रशासन का आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने नियमों का उल्लंघन कर गालिब लॉन में जबरन घुसने का प्रयास किया और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वर्ष 2006 से छात्रसंघ चुनावों पर

लगा यह प्रतिबंध पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और वे अपनी मांगों पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे।

उर्दू टाइम्स (20 अक्टूबर) के अनुसार जामिया प्रशासन ने आंदोलनकारी छात्रों की मांगों और कैंपस की स्थिति पर बातचीत करने के लिए सात सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हालांकि, कैंपस में बने मौजूदा तनावपूर्ण माहौल, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और छात्रों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई के कारण इस वार्ता में फिलहाल कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है।

इंकलाब (20 अक्टूबर) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की घटना पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन की आड़ में छात्रों द्वारा निर्वाचित छात्रसंघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले 20 सालों से छात्रसंघ अस्तित्व में नहीं है।

हमारा समाज (19 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में सवाल उठाया है कि आखिर जामिया प्रशासन छात्रों से इतना भयभीत क्यों है कि उसने 20 सालों से छात्रसंघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगा रखा है। हैरानी की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ की बहाली की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ न सिर्फ निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई की गई है, बल्कि उनके खिलाफ कड़े अनुशासनात्मक कदम भी उठाए गए हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है कि उसने पिछले 20 सालों से छात्रसंघ के चुनावों पर क्यों प्रतिबंध लगा रखा है। समाचारपत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपनी जिद छोड़कर समझौता वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करना चाहिए।

आजम खान और जौहर ट्रस्ट पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज



इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के फंड में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच पूरी कर ली है। इसके बाद 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीमनगर थाने में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कई व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61, 316(5), 318(4) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी पंकज पंत को दी गई है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण में सरकारी ठेकों, निर्माण सामग्री और ट्रस्ट को मिलने वाले अनुदान में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जानी जरूरी है।

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार जिला मूल्यांकन अधिकारी की 10 नवंबर 2023 की रिपोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में निर्माण की अनुमानित

लागत 494.46 करोड़ आंकी गई थी। इसके विपरीत वर्ष 2013-2014 से 2024-2025 तक ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में केवल 78.32 करोड़ रुपये के खर्च की जानकारी दी गई है। इस तरह दोनों के बीच 416.14 करोड़ रुपये का अंतर है, जिसके बारे में व्यापक जांच की जानी जरूरी है।

जांच में जौहर ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों ने यह दावा किया है कि उन्हें कार्यकारिणी समिति की बैठक के बारे में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और न ही वे कार्यसमिति द्वारा किए गए फैसलों में भागीदार थे। ट्रस्ट और उसके वित्तीय संसाधनों पर पूरी तरह से आजम खान का नियंत्रण था। ईडी की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि जब आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में थे तब उन्होंने कुछ ठेकेदारों को ठेके दिलाए थे, लेकिन इन ठेकों के तहत खरीदी गई निर्माण सामग्री का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण में किया गया था।

इस संबंध में ईडी की रिपोर्ट में सीके एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन कुमार जैन के 18 सितंबर 2026 को दर्ज



किए गए बयान का हवाला दिया गया है। इस बयान में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी को वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 के दौरान लगभग 186 करोड़ के सरकारी ठेके मिले थे, लेकिन इन ठेकों की 30 से 40 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण सामग्री खरीदने हेतु किया गया था। ईडी ने इस बयान के आधार पर दावा किया है कि 55.8 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का अनुचित इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए किया गया है।

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश जल निगम के सीएंडडीएस यूनिट के 18 अधिकारियों के बयानों का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने यूनिवर्सिटी परिसर में एक भव्य पंडाल, ओबीसी छात्रों के हॉस्टल और अस्पताल निर्माण के लिए 23.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन 20 अक्टूबर 2016 को इन भवनों का स्वामित्व अनुचित ढंग से यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार 85.81 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का इस्तेमाल अवैध रूप से इस यूनिवर्सिटी की इमारतों के निर्माण के लिए किया गया था। ईडी की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया

गया है कि आजम खान ने एक मंत्री के रूप में कई ठेकेदारों को सरकारी ठेके दिए और उनसे यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए दान राशि प्राप्त की। इस संबंध में रिपोर्ट में एएस इंटरप्राइजेज का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस फर्म को 25 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए थे और बदले में इससे 40 लाख रुपये का चंदा लिया गया। इसी तरह के आरोप दो अन्य कंपनियों पर भी लगाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित आर्थिक अनियमितताओं का यह मामला वर्ष 2019 में तब प्रकाश में आया था, जब रामपुर के तत्कालीन भाजपा नेता और वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में सरकार से शिकायत की थी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की जमीन और शत्रु संपत्ति की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा करके इस यूनिवर्सिटी की इमारतों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में बंद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से कानूनी मुकदमों से घिरी हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी अधिकांश भूमि पहले ही अपने नियंत्रण में ले चुकी है।

गौरतलब है कि इस यूनिवर्सिटी की नींव 18 सितंबर 2006 को रखी गई थी। तब आजम खान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि, बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चले जाने के कारण इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कार्यक्रम खटाई में पड़ गया था। वर्ष 2012 में जब राज्य में समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी तब 18 सितंबर 2012 को इस यूनिवर्सिटी का विधिवत उद्घाटन किया गया था।

कोलकाता हवाई अड्डे की मस्जिद में नमाज पर रोक जारी



इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में स्थित बांकड़ा मस्जिद में नमाज अदा करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ के समक्ष बांकड़ा मस्जिद कमेटी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें हवाई अड्डा परिसर में स्थित इस मस्जिद में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से यह अनुरोध किया था कि मस्जिद में दोबारा नमाज शुरू करने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील किशोर दत्त ने बताया कि पहले नमाजियों को सुरक्षा जांच के बाद ही इस मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। उन्होंने कहा कि नमाज के समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसफ) की देखरेख में एक विशेष बस द्वारा नमाजियों को लाकर मस्जिद तक पहुंचाया

जाता था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस पुराने नियम को जारी रखा जाए।

दूसरी ओर, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से अदालत में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि यह मस्जिद हवाई अड्डे के संवेदनशील परिचालन क्षेत्र के भीतर स्थित है और रनवे से इसकी दूरी मात्र 165 मीटर है। नागर विमानन सुरक्षा

ब्यूरो ने इस मस्जिद को विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। अथॉरिटी ने कहा था कि उच्च सुरक्षा वाले इस क्षेत्र में आम लोगों के प्रवेश के कारण हवाई अड्डे को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अथॉरिटी ने इस संदर्भ में हाल ही में हुई फ्लाईडुबई विमान की सुरक्षा संबंधी घटना का भी हवाला दिया। इस पर मौखिक टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि हवाई जहाजों की सुरक्षा की समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है।

गौरतलब है कि यह मस्जिद लगभग 136 साल पुरानी है। मस्जिद प्रबंधन कमेटी के अनुसार हवाई अड्डे के निर्माण से पहले ही यह मस्जिद वहां मौजूद थी। बता दें कि इसी वर्ष जुलाई महीने में एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से इस मस्जिद में किसी के भी प्रवेश पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

तेलंगाना में मदरसों और मुस्लिम संगठनों की जांच शुरू

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार तेलंगाना सरकार के निर्देशों पर पुलिस और खुफिया विभाग

ने राज्य भर में संचालित इस्लामिक मदरसों, मुस्लिम संस्थानों और तब्लीगी जमात के केंद्रों के



जानकारी जुटाना सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। पुलिस यह जानकारी इसलिए इकट्ठा कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राज्य के मदरसों में कितने विदेशी मूल के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके संचालन के लिए देश व विदेश के किन स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

जानकारी के अनुसार पुलिस राज्य के मदरसों और मुस्लिम संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा पढ़ रहे छात्रों के आधार

कार्ड के विवरण के अतिरिक्त उनके वित्तीय हिसाब-किताब की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस बात का भी ब्योरा लिया जा रहा है कि मुस्लिम संस्थानों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, उनके आवास की क्या व्यवस्था है और उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षकों की पृष्ठभूमि क्या है। इसके अतिरिक्त खुफिया विभाग यह भी जांच कर रहा है कि इन संस्थानों के संचालक कौन हैं, इनका संचालन किस ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है और क्या वे सरकार से पंजीकृत हैं या नहीं।

बारें में विस्तृत जानकारी एकत्र करने का अभियान शुरू किया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद समेत राज्य के अन्य स्थानों पर खुफिया विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां इन संस्थानों के प्रबंधकों से संपर्क कर वहां कार्यरत कर्मचारियों, उनके आय के साधनों और दानदाताओं के बारे में विस्तृत जांच कर रही हैं।

मुस्लिम संगठनों ने इस सरकारी कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार और उपासना के अधिकारों का मनमाने तरीके से उल्लंघन कर रही है। उनका यह भी कहना है कि इस संबंध में पुलिस या सरकार ने कोई विधिवत लिखित दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।

दूसरी ओर, तेलंगाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड प्रबंधन को देखते हुए यह

हालांकि, मदरसों के प्रबंधकों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने इस जांच से संबंधित उच्चाधिकारियों को लिखित आदेश की कॉपी उन्हें दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। कई जिलों में पुलिसकर्मियों द्वारा फोन करके मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों, यतीमखानों आदि के प्रबंधकों को थाने बुलाया जा रहा है तथा उनसे जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है।

फैसले को चुनौती देने वाली बरेलवी की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमद बावा की अपील खारिज करते हुए उसकी

अहमदाबाद बम धमाके के दोषी की फांसी पर रोक

सहाफत (2 अक्टूबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के दोषी अहमद बावा उर्फ अबू अबूबकर बरेलवी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश गुजरात उच्च न्यायालय के

फैसले को चुनौती देने वाली बरेलवी की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है।

गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमद बावा की अपील खारिज करते हुए उसकी



फांसी की सजा को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को एक गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। साथ ही, निचली अदालत का फैसला गुजराती भाषा में होने के कारण दोषी को उसका अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया गया।

जुलाई 2026 में गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषियों की अपीलें खारिज की थीं। तब अदालत ने धमाकों में मारे गए 56 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा और 200 से अधिक घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया था। उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे की 14 साल सुनवाई के बाद 2022 में विशेष अदालत ने 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उम्रकैद पाने वाले 11 दोषियों को भी मौत की सजा देने की मांग की थी।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 सिलसिलेवार

बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच के दौरान पुलिस ने देश भर से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि इन धमाकों के पीछे आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़े आतंकवादियों का हाथ है।

एक अन्य समाचार के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी गुट 'हरकत उल-हर्ब-ए-इस्लाम' के आरोपी मोहम्मद शहजाद कमाल को जमानत दे दी है। अदालत ने यह जमानत इस आधार पर दी है कि वह पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद है और मुकदमे की लंबी सुनवाई के कारण उसे दोषी ठहराए बिना अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। उस पर चल रहे मुकदमों की जांच और अदालत की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार बर्खास्त



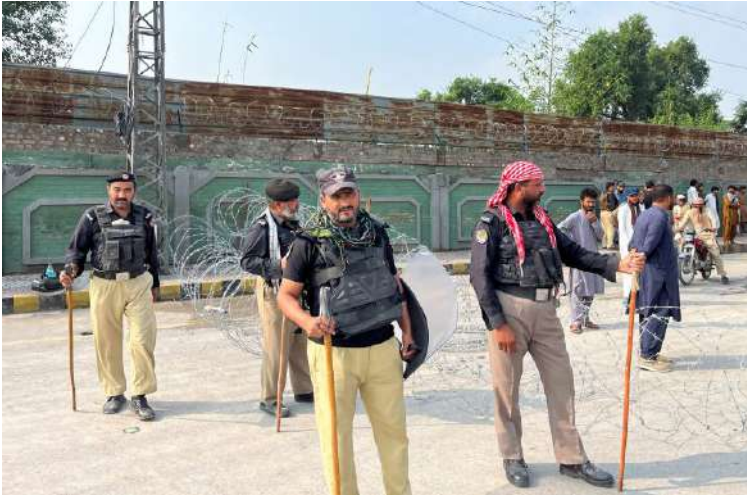
औरंगाबाद टाइम्स (12 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल की घोषणा कर दी है और वहां की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सत्ता में थी। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने यह कदम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत उठाया है।

पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार का कहना है कि संघीय सरकार ने यह कदम प्रांत में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और उनके उन्मूलन में प्रांतीय सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण उठाया है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने प्रांत के संवेदनशील क्षेत्रों को सीधे अपने नियंत्रण में ले

लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भारी संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है और मुख्य शहरों में सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं। इसके साथ ही पीटीआई के उन वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है, जिनके जरिए प्रस्तावित लॉन्ग मार्च का प्रचार किया जा रहा था।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों की तुलना में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमलों और हिंसक घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण प्रांत की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए संघीय सरकार को आपातकालीन कदम उठाना पड़ा है।

प्रांत में आपातकाल लागू होने के बाद अब वहां का प्रशासन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से संबंधित राज्यपाल फ़ैसल करीम कुंडी चलाएंगे। उनकी सहायता के लिए एक 11 सदस्यीय



सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्यपाल ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किए हैं। संघीय सरकार ने निवर्तमान मुख्य सचिव शहाब अली शाह को पेशावर से हटाकर इस्लामाबाद स्थानांतरित कर दिया है। उनकी जगह डॉ. मोहम्मद फखरे आलम इरफान को खैबर पख्तूनख्वा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त नए आपातकालीन प्रशासनिक ढांचे के तहत चिन्हित किए गए प्रांत के 12 जिलाधिकारियों को इस्लामाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह प्रांत के 24 पुलिस कप्तानों और पुलिस महानिरीक्षक को भी प्रांत से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने प्रांत में मोबाइल, इंटरनेट, रेल और बस सेवाओं को निलंबित कर दिया है तथा सभी स्कूल और कॉलेज अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं।

ताजा समाचारों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के निवर्तमान मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के अध्यक्ष गौहर अली खान ने इस्लामाबाद में दावा किया है कि गिरफ्तार होने वालों में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर, विधानसभा अध्यक्ष बाबर

सलीम स्वाती और फेडरल असेंबली के 20 सांसद भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने सड़कों पर आवागमन रोकने के लिए कंटेनर लगा दिए हैं और विरोध करने वालों को देखते ही गोली मारने की घोषणा की है। पीटीआई के महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी

के अध्यक्ष अली अहमद कुर्द ने इस फैसले को तानाशाही का सबूत बताते हुए कहा कि इसका जवाब पाकिस्तान की जनता देगी।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रांत में पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर, देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि देश को आतंकवाद से बचाने के लिए यह निर्णय जरूरी था। इस बीच आपातकाल की घोषणा की पुष्टि के लिए पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया है।

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार 'जंग' ने दावा किया है कि देश में पीपुल्स पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक बार आपातकाल लगाया गया है। अब तक पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में कुल 13 बार राज्यपाल शासन लग चुका है। पाकिस्तान के इतिहास में अक्टूबर का महीना हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक रहा है। 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या के बाद देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1954 को तत्कालीन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने

संविधान सभा को भंग कर देश में आपातकाल लागू किया था। 7 अक्टूबर 1958 को पहली बार राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा देश में मार्शल लॉ लागू किया गया और 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान सैन्य तानाशाह बने। इसी तरह 12 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट कर देश की कमान संभाली थी।



एतेमाद (15 अक्टूबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने और राज्यपाल शासन लगाने के संघीय सरकार के प्रस्ताव को पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से मंजूरी दे दी है। जब सरकार की ओर से सदन में इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच करीब चार घंटे तक तीखी बहस हुई। इस दौरान सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई और इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया।

पीटीआई ने प्रांत में राज्यपाल शासन और आपातकाल लगाने के इस फैसले को पेशावर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। यह याचिका पीटीआई के अध्यक्ष गौहर अली खान की ओर से उनके वकीलों द्वारा दायर की गई है।

नेशनल असेंबली के अधिवेशन में विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई ने संघीय सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सैन्य संस्थानों के समर्थन से लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित खैबर पख्तूनख्वा सरकार को गैर-कानूनी तरीके से बर्खास्त किया है।

उन्होंने दावा किया कि सेना ने देश के 24 करोड़ लोगों में आतंक फैला रखा है। अचकजई ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि सेना की मनमानी के कारण बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान से अलग हो चुका है और अगर अब भी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में यही रवैया बनाए रखा तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तान में रहना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 23 हजार नौकरशाह ऐसे हैं, जिनके पास दोहरी नागरिकता है। वे देश को लूटकर कनाडा, अमेरिका और सऊदी अरब भाग जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या करवाना चाहते हैं।

महमूद खान अचकजई के इस बयान पर सदन में काफी हंगामा हुआ और अध्यक्ष ने उनके भाषण के इस अंश को सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं।

अजरबैजान के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध

एतेमाद (13 अक्टूबर) के अनुसार मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के सरकारी स्कूलों में हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया

गया है। सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि नए ड्रेस कोड नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी छात्रा या महिला शिक्षक को शिक्षण



मंत्रालय ने तुर्किये के बाकू स्थित राजदूत को तलब करके उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि तुर्किये को अजरबैजान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी तुर्किये का बिना नाम लिए कहा कि “हर किसी को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। वे

संस्थान के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। इस फैसले के विरोध में राजधानी बाकू और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आलोचकों का कहना है कि सरकार का यह कदम बच्चों के शिक्षा के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। सरकार को मुसलमानों के शरिया कानूनों और इस्लामिक मूल्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने साफ कहा है कि जब तक यह पाबंदी लागू रहेगी, वे अपनी बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं भेजेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने देशभर के अभिभावकों से एकजुट होकर इस प्रतिबंध का विरोध करने और सरकार को इसे वापस लेने के लिए विवश करने का अनुरोध किया है।

उर्दू टाइम्स (15 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये सरकार ने अजरबैजान सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि यह कदम जहालत (अज्ञानता) की ओर बढ़ने जैसा है। दूसरी ओर, अजरबैजान के विदेश

हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही हमारे रहन-सहन के तौर-तरीकों में अपनी टांग अड़ाएं। हर किसी को अपने देश और अपनी जनता की चिंता करनी चाहिए।”

समाचारपत्र के अनुसार दुनिया के कई देशों में हिजाब, नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध लागू है। यूरोप में इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में फ्रांस से हुई थी, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2015 में इटली ने अपने कुछ क्षेत्रों और अस्पतालों में बुर्के व नकाब पर रोक लगाई थी। इसके बाद सितंबर 2026 में इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक नया अध्यादेश पारित कर देश के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में भी बुर्के तथा नकाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ष 2016 में नीदरलैंड में भी इस प्रतिबंध को लागू किया गया था।

जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल ने वर्ष 2016 में कहा था कि जहां भी कानूनी रूप से संभव हो, बुर्के और नकाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसके बाद वर्ष 2017 में जर्मनी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में चेहरा ढकने वाले लिबास पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया, नार्वे और डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में सार्वजनिक स्थानों व शिक्षण संस्थानों में



बुर्के, नकाब तथा हिजाब पर प्रतिबंध है। यहां तक कि कई इस्लामिक देशों—जैसे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया, मिस्र, सीरिया, कोसोवो, अल्जीरिया और मोरक्को के स्कूलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी बुर्के, नकाब व हिजाब पर प्रतिबंध लागू है।

इंकलाब (15 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में अजरबैजान के स्कूलों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान सरकार इस्लाम विरोधी नीति अपना रही है, जबकि वहां की लगभग 96 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है। हालांकि, सोवियत संघ से आजादी मिले एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन वहां के तानाशाह राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के दिमाग में अब भी इस्लाम विरोध कूट-कूटकर भरा हुआ है। खास बात यह है कि अजरबैजान के पाकिस्तान और तुर्किये जैसे इस्लामिक देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। इसके बावजूद दुनिया भर के धार्मिक मुसलमान इस इस्लाम विरोधी नीति के खिलाफ हैं, क्योंकि वे इसे गैर-इस्लामिक, अलोकतांत्रिक और तानाशाही मानते हैं।

दूसरी ओर, तुर्किये अब मुस्तफा कमाल पाशा का वह पुराना देश नहीं रहा है, जहां उन्होंने इस्लाम विरोधी ईसाई देशों के तुष्टिकरण के लिए पारंपरिक इस्लामिक लिबास पर प्रतिबंध लगाया था। अजीब बात यह है कि इस हिजाब प्रतिबंध

के मामले में अजरबैजान में भी इजरायल का प्रभाव काफी हद तक दिखाई दे रहा है। अजरबैजान के इस गैर-इस्लामिक कानून के खिलाफ सऊदी अरब, इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और खाड़ी सहयोग परिषद समेत सभी इस्लामिक देश और संगठन एकजुट हैं, क्योंकि वे इसे इस्लाम और शरिया के बिल्कुल खिलाफ मानते हैं। हैरानी की बात है कि इजरायल के साथ अजरबैजान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन घनिष्ठता आ रही है। आज इजरायल, अजरबैजान को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। समाचारपत्र ने मांग की है कि अजरबैजान सरकार को अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले लेना चाहिए ताकि इस्लाम, कुरान और शरिया का वर्चस्व बरकरार रह सके।

इंकलाब (11 अक्टूबर) के अनुसार ब्रिटेन में सोमालिया मूल की एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला सांसद चुनी गई हैं। यह सीट पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सत्ताधारी लेबर पार्टी ने इस चुनाव में सोमाली मूल की महिला सगल अब्दी-वली को मैदान में उतारा था। उन्हें इस चुनाव में 12 हजार से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी ग्रीन पार्टी के नेता को शिकस्त दी है। अपनी जीत पर टिप्पणी करते हुए अब्दी-वली ने कहा कि वे एक मुसलमान हैं और अपनी धार्मिक आस्था का पालन करते हुए हिजाब पहनती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे ब्रिटिश संसद में भी इसी हिजाब को पहनकर जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी इस ऐतिहासिक जीत से यह साबित हो गया है कि ब्रिटिश मतदाता सेक्युलर हैं और वे धर्म या पहनावे के आधार पर भेदभाव न करके योग्यता के आधार पर अपना मत देते हैं।

तालिबान नेताओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का वारंट



औरंगाबाद टाइम्स (7 अक्टूबर) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा, मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी, शिक्षा मंत्री हबीबुल्लाह आगा और उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन नेताओं पर 15 अगस्त 2021 से 20 जनवरी 2025 के बीच हत्या, यातना, बलात्कार, जबरदस्ती गायब करने और महिलाओं के उत्पीड़न

जैसे मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं। अदालत इससे पहले 2025 में भी तालिबान के 12 उच्चाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है।

इस पर टिप्पणी करते हुए तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि “हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कोई कीमत नहीं है और यह वारंट महज कागज के टुकड़े हैं, जिन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है और हम यहां शरिया कानूनों को

लागू कर रहे हैं। पश्चिमी देश इस्लाम व शरिया के दुश्मन हैं और उन्हें हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश शरिया तथा इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। हम अपने देश में शरिया कानूनों को लागू करने हेतु कटिबद्ध हैं और हम इस मामले में किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक इस देश में जो भी फैसले हुए हैं, वे सभी इस्लामिक शरिया के अनुरूप ही हुए हैं।”

बांग्लादेश में सैकड़ों विपक्षी नेता गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (8 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जातीय समाजतांत्रिक दल के केंद्रीय कार्यालय से लगभग 300 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के युवा संगठन ‘जुबो दल’ ने यह दावा किया है कि इस पार्टी की आड़ में शेख हसीना की प्रतिबंधित पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग को

पुनर्जीवित किया जा रहा है और यह उसी पार्टी का एक गुप्त अधिवेशन था। इसके अतिरिक्त ढाका में ‘जॉय बांग्ला’ का नारा लगाने के आरोप में 27 अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिनका संबंध अवामी लीग से बताया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि जातीय समाजतांत्रिक दल उस 14 दलीय गठबंधन का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व अवामी लीग कर रही थी। यह गठबंधन 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहा। हाल ही में बांग्लादेश पुलिस ने



बारिसाल में अवामी लीग के 12 कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप है कि वे अवामी लीग की एक गुप्त बैठक में भाग ले रहे थे। इससे कुछ दिन पहले ढाका में खुफिया पुलिस ने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत छापेमारी कर 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि ये लोग अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का जन्मदिन मनाने और तोड़फोड़ की साजिश रचने के लिए इकट्ठा हुए थे।

शेख हसीना के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया है कि बांग्लादेश

की वर्तमान सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर अब तक चार हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से अपनी हिरासत में ले चुकी है। छह महीने गुजर जाने के बावजूद उनके खिलाफ न तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, न ही उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर की गई है। अवामी लीग ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद कर रही है।

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने निमंत्रण दिए जाने के बावजूद भारत में आयोजित ब्रिक्स आउटरीच सम्मेलन का बहिष्कार किया था। बांग्लादेश सरकार के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि बांग्लादेश के गृह मंत्री ने इस दौरे का बहिष्कार दोनों देशों के आपसी संबंधों में आई कटुता के कारण किया है।

13 अमेरिकी सैनिकों के हत्यारे मुस्लिम मेजर को मृत्युदंड

सियासत (10 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक विशेष आदेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत 13 अमेरिकी सैनिकों के हत्यारे मुस्लिम मेजर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड (सैनिक दस्ते) द्वारा गोली मारकर मृत्युदंड दिया जाएगा। आमतौर पर अमेरिका में हत्यारों को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा जाता है। अमेरिकी इतिहास में पिछले 80 सालों में यह सेना द्वारा दी जाने वाली पहली मौत की सजा होगी और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार

किसी सैनिक को फायरिंग स्क्वाड का सामना करना होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय टेलीविजन और इंटरनेट पर इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि निदाल हसन ने साल 2009 में अमेरिकी राज्य टेक्सास के किलीन शहर में स्थित सैन्य अड्डे फोर्ट हुड में अंधाधुंध गोलीबारी करके 13 निहत्थे अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी और 30 से अधिक लोगों को घायल कर दिया था। उसे इस हत्याकांड का दोषी



करार देते हुए सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार हत्यारे को उसी स्थान पर मौत के घाट उतारा जाएगा, जहां उसने अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 अक्टूबर) के अनुसार हत्यारा अमेरिकी सेना में मनोचिकित्सक के रूप में काम करता था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने संवाददाताओं को बताया कि जिस तरीके से इस मुस्लिम व्यक्ति ने अमेरिकी सैनिकों की सामूहिक हत्या की थी, उसे देखते हुए यह जरूरी है कि उसे फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मारने के दृश्य को लाइव स्ट्रीम के जरिए अमेरिकी जनता के सामने पेश किया जाए।

कौमी तंजीम (14 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी संघीय एजेंसी 'होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस' ने वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई का संबंध उनके नागरिकता और प्रवासन दस्तावेजों में धोखाधड़ी की जांच से है। सोमाली मूल की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर को राष्ट्रपति ट्रम्प के कट्टर विरोधी नेताओं में गिना जाता है। हाल ही में ट्रम्प ने सोमाली मूल के प्रवासियों को निशाना बनाते हुए उन्हें अमेरिका के लिए खतरा बताया था। इससे पहले उन्होंने मिशिगन से अमेरिकी सीनेट चुनाव के लिए नामांकित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद को भी

जिहादी और अमेरिका के लिए खतरनाक करार दिया था। फरवरी में भी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि इल्हान उमर और मिशिगन की सांसद रशीदा तालिब को उनके मूल देशों में वापस भेज दिया जाना चाहिए।

इन राजनीतिक हमलों के बीच इल्हान उमर ने आरोप लगाया था कि ट्रम्प समर्थक अतिवादी उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल के जनवरी महीने में एंथनी

जेम्स नामक एक व्यक्ति ने इल्हान उमर को अमेरिका के लिए खतरा बताते हुए उन पर तेजाब फेंककर हत्या करने का प्रयास किया था, जिसे अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई थी।

उर्दू टाइम्स (16 अक्टूबर) के अनुसार ट्रम्प प्रशासन डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर की अमेरिकी नागरिकता को रद्द करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने लिखा है कि अमेरिका में इल्हान उमर के प्रवेश के समय उनके पिता ने उनकी आयु गलत बताई थी। उन्होंने यह दावा किया था कि इल्हान की उम्र 17 वर्ष है। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि वे स्वयं एक अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए नाबालिग होने के कारण इल्हान अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं। अमेरिकी एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार सरकार ने एक अदालती वारंट के तहत इल्हान का पासपोर्ट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।

उल्लेखनीय है कि इल्हान उमर मिनेसोटा क्षेत्र से लगातार पांचवीं बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इल्हान ने 1991 में सोमालिया से भागकर केन्या के एक शरणार्थी शिविर में शरण ली थी। इसके बाद 1995 में वे अमेरिका पहुंचीं और वर्ष 2000 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं।

इराक से अमेरिकी सेना की वापसी



इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी का मिशन सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में इराक सरकार ने पूरे देश में चार दिवसीय 'संप्रभुता दिवस' राष्ट्रीय उत्सव मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत देश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो दशकों से अधिक समय से अमेरिकी सैनिक इराक में तैनात थे। वर्ष 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के शासन के पतन के बाद इराक लंबे समय तक अमेरिकी सेना के नियंत्रण में रहा। हालांकि, अमेरिका ने बाद के वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अपने सैनिकों की संख्या कम करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में इराक में लगभग 1500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जो 2014 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के 'ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व' में इराकी सुरक्षा बलों के लिए सलाहकार और प्रशिक्षण की भूमिका निभा रहे थे।

समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह प्रयास किया था कि इराक की संसद शिया नेता नूरी अल-मलिकी को प्रधानमंत्री न चुने

और उनकी जगह अली अल-जैदी के नाम का समर्थन किया था। अल-जैदी के सत्ता में आने के बाद इराक से अमेरिकी सैनिकों की सम्मानजनक वापसी तय हो गई थी। अमेरिका ने यह भी दबाव डाला था कि जून 2027 तक इराक में सक्रिय ईरानी मिलिशिया का निःशस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि ईरान समर्थित इन सशस्त्र संगठनों ने अमेरिका और इजरायल द्वारा गाजा में छेड़े गए युद्ध के दौरान अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे।

पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार यह प्रयास कर रही है कि इराक में सक्रिय सभी सशस्त्र मिलिशिया गुटों का निःशस्त्रीकरण हो और हथियार केवल इराक की सरकारी सेना के पास ही होने चाहिए। ईरान समर्थक मिलिशिया गुटों द्वारा यह मांग की गई थी कि जब तक इराक में अमेरिकी सेना और तुर्किये के सशस्त्र दस्ते मौजूद रहेंगे तब तक वे अपने हथियार नहीं डालेंगे।

इंकलाब (2 अक्टूबर) के अनुसार इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इराक के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इराकी

सेना देश की रक्षा की बागडोर पूरी तरह संभालने में सक्षम है। ऐसे में यह जरूरी है कि ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन अपने हथियार सरकार के हवाले कर दें। अब वर्तमान परिस्थितियों में इन विदेशी समर्थित मिलिशिया गुटों के पास हथियार रखने का कोई तर्क बाकी नहीं रह गया है। इराक के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन ने देश की रक्षा व्यवस्था और सैन्य कार्रवाइयों की जिम्मेदारी इराकी सेना प्रमुख को सौंप दी है।

ईरानी संगठन पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने इराक से अमेरिकी सेना की वापसी को एक ऐतिहासिक घटना करार दिया है। आईआरजीसी ने कहा है कि वे इस शुभ अवसर पर इराक की जनता और इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट को बधाई देते हैं। अमेरिका ने उनके देश को खाली कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से इराकियों के हवाले कर दी है।

एतेमाद (2 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इराक से अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों की विदाई का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया में अपने स्थायी सैन्य अड्डे स्थापित करने के उद्देश्य से तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर जैविक हथियार रखने का झूठा आरोप लगाकर वर्ष 2003 में इराक पर हमला किया था। वर्ष 2011 में अमेरिकी सेना का एक बड़ा हिस्सा वापस चला गया था, लेकिन तीन साल बाद 2014 में आईएसआईएस के सफाए के बहाने अमेरिकी सेना ने इराक में दोबारा वापसी की थी। उस दौरान ईरान समर्थित मिलिशिया और अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के बीच हुई झड़पों और युद्ध में लगभग साढ़े चार हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए थे,



जबकि दो लाख से अधिक इराकी नागरिक भी इस युद्ध का शिकार बने थे।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों की इस पूर्ण वापसी का सबसे अधिक रणनीतिक लाभ ईरान को होगा। यही कारण है कि ईरान समर्थित मिलिशिया गुट इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। मोटे तौर पर इराकी जनता इस वापसी का स्वागत कर रही है। हालांकि, कुछ लोग यह आशंका भी जता रहे हैं कि यदि इन ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों ने सरकारी निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को ठुकरा दिया तो क्षेत्र में गृहयुद्ध जैसी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इराक सरकार ने भी संकेत दिया है कि आईएसआईएस का खुफिया नेटवर्क अभी भी देश में मौजूद है, जो दोबारा सिर उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 2020 में बगदाद हवाई अड्डे पर एक हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर चुका है, इसलिए वह इराक में ईरान के सीधे सैन्य प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा।

हमारा समाज (4 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि अमेरिकी और ब्रिटिश सेना भले ही इराक से निकल चुकी है, लेकिन वहां ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों की भारी मौजूदगी के कारण कुर्द समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। इराक में शिया, सुन्नी और कुर्दों के

बीच वर्ष 2003 से ही आंतरिक संघर्ष जारी है। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में बंदूक किसके हाथ में होगी। हालांकि, इराक सरकार को उम्मीद है कि ईरान समर्थित सशस्त्र समूह अपने हथियार सरकारी सेना को सौंप देंगे, लेकिन मिलिशिया गुटों के

अडियल रवैये को देखते हुए इसकी संभावना कम दिखती है। यदि इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर आईएसआईएस फिर से पैर जमाने की कोशिश करता है तो उसका सीधा टकराव कुर्दों से होगा, जिससे इस क्षेत्र में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है।

भारतीय पायलट की बहादुरी से टला विमान अपहरण



इंकलाब (3 अक्टूबर) के अनुसार फ्लाईदुबई विमान में सह-पायलट द्वारा मुख्य पायलट पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में सऊदी अरब सरकार ने आरोपी को हिरासत में लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार के हवाले कर दिया है। यह घटना तब हुई जब दुबई से तेल अवीव जा रहे इस विमान के कॉकपिट में ओमान मूल के सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने भारतीय मूल के मुख्य पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और विमान का नियंत्रण छीनने का प्रयास किया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के

अनुसार शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि उड़ान के दौरान सह-पायलट ने ही मुख्य पायलट पर यह हमला किया था। हमले के बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित उतारा गया।

सऊदी सरकार ने दोनों घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार और डॉक्टरों से मंजूरी मिलने के बाद आरोपी अल-हम्मामी को यूएई की सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया, जबकि स्मित मच्छार को आगे के इलाज के लिए अरब धाबी भेज दिया गया है। विमान में सवार सभी 174 यात्री पूरी तरह सुरक्षित



हजार फीट की उंचाई पर उड़ रहा था, अचानक तेजी से गिरकर 17 हजार फीट पर आ गया था, जिससे विमान और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। बाद में विमान में सवार दो अन्य पालयटों की सहायता से इस विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।

हैं, जिनमें अधिकांश इजरायली नागरिक थे। इन यात्रियों को बाद में एक अन्य विमान के जरिए तेल अवीव भेज दिया गया।

कौमी तंजीम (5 अक्टूबर) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अल-हम्मामी को 'इस्लाम का हीरो' करार दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा के मुखपत्र 'अल-बयान' ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ उनका युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इस पत्रिका में अमेरिका और इजरायल के यात्री विमानों पर 11 सितंबर 2001 जैसे और हमले करने की चेतावनी दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस्लाम विरोधी रुख रखने वाले देशों को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें लगातार निशाना बनाया जाएगा। इस खबर के साथ न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (ट्विन टावर्स) से टकराने वाले विमान की तस्वीर भी प्रकाशित की गई है।

सहाफत (2 अक्टूबर) के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सह-पायलट अल-हम्मामी इन यहूदी यात्रियों के बदले इजरायल की जेलों में बंद कुछ अरब आतंकवादियों को रिहा करवाना चाहता था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी और कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और केबिन क्रू की मदद से अल-हम्मामी पर काबू पा लिया गया। इस संघर्ष के दौरान विमान, जो 33

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खुलकर प्रशंसा की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कैप्टन स्मित मच्छार मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और उनका परिवार मुंबई में रहता है, जबकि वर्तमान में वे यूएई के निवासी हैं। वे 11 वर्षों तक स्पाइसजेट एयरलाइंस में कार्यरत थे, जिसके बाद जून 2022 में उन्होंने फ्लाईडुबई एयरलाइंस में काम करना शुरू किया था। उनके पास 13 वर्षों से अधिक का वाणिज्यिक उड़ान का अनुभव है।

इंकलाब (4 अक्टूबर) के अनुसार यूएई सरकार ने फ्लाईडुबई विमान की घटना को एक आतंकवादी हमला करार दिया है। सरकारी सूचना के अनुसार सह-पायलट अल-हम्मामी ने आतंकवादी मंशा से इस हमले और विमान का अपहरण करने की योजना पहले से ही बना रखी थी। इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है।

सियासत (4 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला करार दिया है। ओमान के सरकारी सूत्रों के मुताबिक हमाम अल-हम्मामी ने ओमान की वायु सेना और वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस में नौकरी पाने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी आतंकवादी पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार ने उसे प्रतिबंधित कर नौकरी देने से

इनकार कर दिया था। इसके बाद वह यूएई चला गया और वहां फ्लाईदुबई एयरलाइंस में नौकरी पाने में सफल हो गया।

‘अल अरबिया’ की रिपोर्ट के अनुसार 29 वर्षीय अल-हम्मामी ओमान का नागरिक है। उसके पिता ओमानी और मां सीरियाई नागरिक हैं। हम्मामी का जन्म यूएई में हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सीरिया में बिताया और वहीं वह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के संपर्क में आया। वह फ्लाईदुबई में पिछले आठ महीने से काम कर रहा था। इससे पहले वह ‘रॉयल एयर मारोक’ में कार्यरत था।

हमाम अल-हम्मामी का संबंध अल-कायदा से रहा है और उसके पास से ‘फ्री फिलिस्तीन समूह’ का साहित्य भी मिला है। वह इजरायल का घोर विरोधी है। इजरायली मीडिया ने सवाल उठाया है कि आतंकवादी पृष्ठभूमि वाले इस विमान चालक को तेल अवीव आने वाले विमान में किन कारणों से नियुक्त किया गया था? ओमान ने इजरायल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, ऐसी स्थिति में यूएई की सरकार ने उसे इजरायल जाने वाले विमान को उड़ाने की अनुमति क्यों दी? इजरायली मीडिया के अनुसार अल हम्मामी का इरादा विमान पर कब्जा कर उसे इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे के एविएशन टावर से टकराने का था ताकि उसमें सवार सभी यात्री मारे जाएं।

सियासत (16 अक्टूबर) के अनुसार फ्लाईदुबई विमान की घटना के बाद सुरक्षा कारणों से एयर फ्रांस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने मुस्लिम देशों के विमान पायलटों को इजरायल जाने वाली उड़ानों पर नियुक्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल सरकार ने सुरक्षा जांच सख्त करते हुए अपनी हवाई सीमा में ऐसे देशों के विमान चालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं। यह प्रतिबंध उन देशों के



पायलटों पर भी लागू होगा, जहां संबंधित नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता की सुविधा है। इजरायल सरकार ने सभी विमान कंपनियों को इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और विमानन व्यवस्था द्वारा चिन्हित किए गए देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, लेबनान, सीरिया, यमन, सूडान, कोलंबिया समेत 31 देश शामिल हैं। इसी कड़े नियम के चलते हाल ही में इथियोपियन एयरलाइंस के एक विमान को, जिसे इंडोनेशियाई मूल का पायलट उड़ा रहा था, इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

औरंगाबाद टाइम्स (10 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इस घटना के लिए यूएई प्रशासन और फ्लाईदुबई एयरलाइंस को जिम्मेदार ठहराया है। समाचारपत्र ने सवाल उठाया है कि ओमान और इजरायल के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध न होने के बावजूद अल-हम्मामी को तेल अवीव जाने वाले विमान को उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई? समाचारपत्र ने कहा है कि मुख्य पायलट कैप्टन मच्छार पर हमला करने से पहले सह-पायलट द्वारा विमान में नमाज अदा करने की बात सामने आई है, जबकि उड़ान के समय किसी भी नमाज का वक्त नहीं था। समाचारपत्र ने संदेह व्यक्त किया है कि यह पूरा घटनाक्रम इस्लाम को बदनाम करने और इजरायल द्वारा सहानुभूति बटोरने का एक सुनियोजित ड्रामा भी हो सकता है।

सऊदी अरब और हूतियों के बीच छिड़ी भीषण जंग



इंकलाब (12 अक्टूबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। इस भीषण हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में चार सऊदी नागरिकों के अतिरिक्त बांग्लादेश, अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान के नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने इस हमले की पुष्टि की है और आरोप लगाया है कि हूती विद्रोही लगातार नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही हूतियों द्वारा मक्का और मदीना जैसे पवित्र धार्मिक स्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने 'अल अरबिया' को बताया कि वे मक्का और मदीना जैसे किसी भी पवित्र इस्लामी स्थल पर हमला नहीं कर रहे हैं। सऊदी सरकार द्वारा उन पर लगाए जा रहे ऐसे आरोप केवल उन्हें इस्लामी दुनिया में बदनाम करने की एक साजिश है।

इस हमले के बाद रियाद स्थित हवाई अड्डा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और स्पेन ने अपने

नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों से दूर रहें। संयुक्त राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान सहित 45 देशों ने रियाद हवाई अड्डे पर हमले की कड़ी निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि नागरिकों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह की कार्रवाई फौरन बंद की जानी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और

उनके परिवार सहित कई अन्य भारतीय घायल भी हुए हैं।

यमन के हूती समूह ने विश्व की विमानन कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों और वायु सीमा का इस्तेमाल न करें, अन्यथा उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हूती प्रवक्ता ने आश्वस्त किया कि वे किसी भी कीमत पर मक्का और मदीना को निशाना नहीं बनाएंगे।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है कि हूती मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों को रोकने में उसकी वायु रक्षा प्रणाली क्यों विफल रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक हूतियों ने केवल मिसाइलों का ही नहीं, बल्कि सबसे पहले एक साथ कई आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल किया था ताकि रडार को व्यस्त किया जा सके। इसके बाद उन्होंने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हवाई अड्डे को निशाना बनाया। सुरक्षा के इसी गंभीर खतरे को देखते हुए दुनिया की कई विमानन कंपनियों ने घोषणा की है कि वे सऊदी अरब के लिए अपनी सभी हवाई उड़ानें फिलहाल निलंबित रखेंगी।



एक अन्य समाचार के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने हूती हमलों के दौरान सऊदी अरब की सहायता के लिए अपने कुछ अत्याधुनिक विमान सऊदी अरब भेजे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में ब्रिटेन के कुछ सैन्य अड्डों पर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है, उसके पीछे ईरान का हाथ पाया गया है। इन हमलों का संचालन आईआरजीसी ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन अपनी भूमि पर इस तरह की किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

बीबीसी के अनुसार हूती प्रवक्ता ने कहा है कि यदि अमेरिका ने इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे रियाद के किंग खालिद और दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित अरामको के तेल संयंत्रों को अपना निशाना बना रहे हैं।

इंकलाब (11 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने हूती नियंत्रित यमन की राजधानी साना पर 'ऑपरेशन यमन डॉन' के तहत भीषण हवाई हमले किए हैं। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान किए गए इन हमलों में 700 से अधिक हूती विद्रोही मारे गए हैं और

उनके कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के यमन के लिए विशेष दूत हैंस ग्रुंडबर्ग ने सुरक्षा परिषद को सचेत किया है कि यमन में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर भीषण युद्ध छिड़ गया है, जो कई मोर्चों पर फैल चुका है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि इस क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके।

इंकलाब (9 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा हूतियों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए यमन में अपने सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के सैनिकों की मदद करना है ताकि वे उन क्षेत्रों पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें, जिन पर हूतियों ने हाल ही में कब्जा किया है। इस संबंध में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों को हाल ही में भारी मात्रा में चीन निर्मित बैलिस्टिक मिसाइलों के विभिन्न कल-पुर्जे



नागरिक ठिकानों पर हूतियों द्वारा किए गए हमलों की निंदा की है। उसने सभी अरब देशों से इस नाजुक घड़ी में सऊदी अरब सरकार के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की है। वहीं, मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस संकट में सऊदी अरब को हर संभव सहायता देने की प्रतिबद्धता

प्राप्त हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक हूती विद्रोही चीन से आयातित इन पुर्जों को जोड़कर उन्नत और लक्ष्य तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन मिसाइलों से न केवल सऊदी अरब, बल्कि इजरायल को भी निशाना बनाया जा सकता है।

उर्दू टाइम्स (10 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ उनका सैन्य गठबंधन है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह एक आक्रामक समझौता नहीं, बल्कि रक्षात्मक समझौता है, इसलिए तुर्किये किसी भी अन्य देश पर हमला करने या आक्रामक अभियानों में सऊदी अरब की सहायता करने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान ने हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब को सहायता देने की घोषणा की है। सऊदी अरब ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तानी सैनिक और लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस संबंध में पाकिस्तान के उच्च सैन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के बीच विस्तृत बातचीत हो चुकी है।

सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार अरब लीग ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और

व्यक्त की है।

औरंगाबाद टाइम्स (6 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने घोषणा की है कि 'ऑपरेशन यमन डॉन' के शुरुआती चरण में 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है, जो हूतियों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।

सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत हूतियों को आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

हिंदुस्तान (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि अमेरिका जानबूझकर अरब देशों को युद्ध की ओर धकेल रहा है। संपादकीय में ईरान से अनुरोध किया गया है कि वह इस युद्ध को रोकने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप करे। संपादकीय में यह भी उल्लेख किया गया है कि सऊदी अरब और हूतियों के बीच यह संघर्ष वर्ष 2015 से जारी है। हालांकि, यमन संकट की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हूतियों ने सितंबर 2014 में यमन की राजधानी साना सहित देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था।

सऊदी अरब में रसूल के अपमान पर सुनाई गई मौत की सजा रद्द



हिंदू देवता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट कर दी। इसके जवाब में अनोजन सिवरासा ने तमिल भाषा में पैगंबर-ए-इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी। हालांकि, अनोजन ने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर माफीनामा वीडियो भी जारी कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर सऊदी प्रशासन और उस कंपनी को ईमेल कर

चट्टान (15 अक्टूबर) के अनुसार श्रीलंका के उप-विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब की सर्वोच्च अदालत ने एक श्रीलंकाई नागरिक को फेसबुक पर की गई टिप्पणी के कारण मिली मौत की सजा को रद्द कर दिया है। 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर अनोजन सिवरासा को सितंबर 2026 में सऊदी अरब की एक अपीलीय अदालत ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में मृत्युदंड सुनाया था। इस फैसले के विरोध में श्रीलंका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके बाद मानवाधिकार संगठनों और वहां की सरकार ने राजनयिक व कानूनी स्तर पर इस मृत्युदंड को रूकवाने के प्रयास शुरू किए थे।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब हिंदुओं की एक तीर्थयात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने तीर्थयात्रियों के साथ चल रहे एक कुत्ते को लात मार दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में हिंदू और मुस्लिम युवकों के बीच ऑनलाइन बहस छिड़ गई। इस बहस के दौरान एक अन्य मुस्लिम युवक ने

दिया जहां अनोजन काम करते थे। इसके बाद कंपनी द्वारा सूचना दिए जाने पर सऊदी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

15 जुलाई को अल-अहसा की एक अदालत ने अनोजन को साइबर अपराध कानून के तहत पांच साल की जेल और 30 लाख सऊदी रियाल जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन 17 सितंबर को सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी कि साइबर कानून के तहत सुनाया गया यह फैसला शरिया के अनुरूप नहीं है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी ने पैगंबर का अपमान किया है, इसलिए यह मामला शरिया अदालत में चलना चाहिए। अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार कर यह मुकदमा शरिया अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जिसने शरिया कानून के तहत पैगंबर के अपमान के आरोप में अनोजन को मौत की सजा सुना दी। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के दबाव तथा श्रीलंका सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी अरब की सर्वोच्च अदालत ने इस मृत्युदंड को पूरी तरह रद्द कर दिया।

मोरक्को में पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त



मोरक्को के शाह ने यह नियुक्ति देश में सितंबर महीने में हुए संसदीय चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद की है। एल मंसूरी की नेतृत्व वाली 'ऑर्थेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी पार्टी' (पीएम) ने इन चुनावों में सर्वाधिक 97 सीटें जीती हैं। हालांकि, 395 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत न मिल पाने के कारण वे अन्य दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार का गठन करेंगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में शाह के करीबी सलाहकार फौद अली एल हिम्मा ने पीएम पार्टी की नींव रखी थी। दूसरी ओर, 'जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी' और 'फेडरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक लेफ्ट' सहित छह दलों ने विपक्ष में बैठने की घोषणा करते हुए किसी भी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने से इनकार किया है।

फातिमा एज्जहरा एल मंसूरी का जन्म वर्ष 1976 में हुआ था। उन्होंने फ्रांस के मोंटपेलियर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से 'एंग्लो सैक्सन बिजनेस लॉ' में डिप्लोमा भी हासिल किया है।

इंकलाब (1 अक्टूबर) के अनुसार मोरक्को के शाह (सम्राट) मोहम्मद षष्ठम ने फातिमा एज्जहरा एल मंसूरी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे ट्यूनीशिया की नजला बौडेन के बाद अरब जगत में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। शाही महल से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार 50 वर्षीय एल मंसूरी को नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इससे पहले मराकेश की मेयर और कई विभागों की मंत्री रह चुकी हैं। नियुक्ति के बाद सरकारी टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए एल मंसूरी ने इसे ऐतिहासिक और देश की सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण बताया।

